(ख) सरकार द्वारा बीड़ी को लोकप्रिय बनाने और विदेशों को इसके निर्यात में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां।

(ख) बीड़ियों का निर्यात बढ़ाने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा किए गए उपायों में ये शामिल हैं--अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में बीड़ियों के विभिन्न ब्राण्ड प्रदर्शित करना, व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों के दौरों के समय थ्रस्ट बाजारों का पता लगाना, बाजार सर्वेक्षण करना और विदेशी स्रोतों से प्राप्त निर्यात पूछताछों को बीड़ी निर्यातकों तक पहुंचाना। किन्तु बीड़ियों का निर्यात बढ़ाना कठिन हो रहा है क्योंकि पश्चिम एशिया के देशों में बीड़ियों का धूम्रपान अधिकांशतया भारतीय जाति के लोगों द्वारा किया जाता है।

Structural Changes in MMTC

1913. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a newsitem published in the Financial Express of 29th June, 1992 captioned "MMTC effecting major structural changes" in the functioning of the organisation;

(b) if so, what are the details thereof, indacting the steps taken for improvement of quality management so as to be able to survive in the competitive world market; and

(c) what are the proposed new product lines in which the Corporation will engage itself to increase the volume of business and steps likely to be taken in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SALMAN KHURSHEED): (a) Yes, Sir.

(b) MMTC is re-organising itself into specific profit centres consequent upon the decanalisation of a number of items under the new Export and Import Policy so as to improve the quality of management including identifying new markets/products for promotion of exports in the competitive world market and has registered itself with the Confederation of India Industries (CII) for quality improvement and training requirements etc.

(c) Besides traditional items, new thrust is being given to export of agricultural products, pesticides and insecticides, agro chemicals, industr chemicals, drugs and pharmaceuticals forest products biotechnology, marine products cottage & handloom industry, textiles including apparels, leather garments and other leather products, leasing and hire-purchases, warehousing, off-shore trading, merchanising trade and shipping. Thrust and penetration is being increased on existing lines like gem & jewellery, fertilizers, minerals and metals and engineering products and projects.

Creation of new Export Processing Zones

1914. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether any Committee at the industry level or Government level was set-up to study and recommend creation of new Export Processing Zones in the Country, if so, the details of the places/cases studied by the said Committee and the places where Export Processing Zones have already been set-up and proposed to be set-up in the future; and

(b) the status of the report of the committee and action proposed to be taken thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SALMAN KHURSHEED): (a) and (b) A Committee was appointed to examine and propose an alternative model for development of Export Processing Zones (EPZ). The report

of the Committee has been circulated to the concerned departments and Development Commissioners of the EPZs for their views. At present EPZs exist at Gandhidham (Gujarat), Bombay (Maharashtra), Madras (Tamil Nadu), Cochin (Kerala), Noida (UP) and Falta (West Bengal). An EPZ at Visakhapatnam is under development. There is no proposal to set-up additional EPZs.

राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम और प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कारपोरेशन का कार्यकरण

1915. **श्री वीरेन जे० शाह :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **वाणिज्य मंत्री** 21 जुलाई, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 1149 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश म आयात-निर्यात का दायित्व सरकारी क्षेत्र के तीन प्रमुख संस्थानों द्वारा निभायाँ जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन तीनों संस्थानों अर्थात राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम और प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन का कारोबार सरकार की उदार आयात-निर्यात नीति के कारण पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो गत वर्षों की तुलना में वर्ष 1991–92 के दौरान उनके कारोबार में कितनी कमी हुई है; और

(घ) इन संस्थानों में मार्च, 1992 के अंत में कुल कितने लोग कार्यरत थे और इन संस्थानों का वार्षिक बजट कितना-कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) एस टी सी, एम एम टी सी और पी ई सी देश में आयात-निर्यात के दायित्व का वहन करने वाली प्रमुख राज्य व्यापार कंपनियां हैं ।

(ख) और (ग) आयात और निर्यात की मदों का भारी संख्या में सरणीयन समाप्त करने के संदर्भ में इन कंपनियों में अपने निगम उद्देश्यों का पुनर्निर्धारण किया है ताकि वे मुख्य रूप से गैर-सरणीकृत व्यापार पर आधारित प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में कार्य करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार घराने बन सकें ।

पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान एस०टी०सी, एम०एम०टी०सी० और०पी०ई० सी० का कुल कारोबार निम्नलिखित रहा :–

(करोड़ रु० में)

वर्ष	एस०टी०सी	एम०एम०	पी०ई०सी० टी०सी०
1990–91	1756	5622.98	135.47
1991–92	1315	791000 (अनन्तिम)	195.16 (अनन्तिम)

मदो के गैर सरणीकरण के कारण एस०टी०सी० के कारोबार म कुछ कमी आई है लेकिन वित्तीय वर्ष 1991–92 के दौरान वित्तीय वर्ष 1990–91 की तुलना में पी०ई०सी० और एम०एम०टी०सी० के कारोबार में कोई गिरावट नहीं हुई है ।

(घ) दिनांक 31–3–1992 के अनुसार इन कम्पनियों में मानव शक्ति की स्थिति निम्नलिखित थी :–

एस०टी०सी	एम०एम० टी०सी०	पी०ई०सी
1962	3648	259

इन कम्पनियों का वर्ष 1992–93 के लिये अनुमानित निष्पादन लक्ष्य व बजट नीचे दिया गया है :–

(करोड़ रुपयों में)

एस०टी०सी०	एम०एम०टी०सी०	पी०ई०सी०
1525	5587	310.80